

## **Regarding restoration of domicile policy and curtailing the fee of PG courses for youth in Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu**

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : सभापति महोदया, अभी दादरा और नागर हवेली की सांसद जी ने जो मांग रखी है, वही मेरी भी मांग है। देश की आजादी के बाद भी हमारा प्रदेश 14 साल बाद आजाद हुआ था। आज भी हमारे यहां पर यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, बल्कि एसएससी और एचएससी जैसी बुनियादी सुविधा तक नहीं है। हमारा प्रदेश का एजुकेशन स्तर पर बाकी राज्यों से बहुत नीचे है। हमारे यहां पर सरकारी नौकरियों की भर्ती पूरे देश के लिए ओपन होती है इसलिए हमारे प्रदेश के युवाओं को बिना डोमिसाइल के लाभ के नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। हमारे प्रदेश की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति थी। प्रशासन ने डोमिसाइल नीति में संशोधन कर डोमिसाइल की जगह 20 अंक का प्रावधान कर दिया। उसे भी माननीय न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। इस तरह से हमारे प्रदेश में नौकरियों के लिए डोमिसाइल नीति भी खत्म हो गई है। आज स्थिति यह है कि हमारे क्षेत्र की सरकारी भर्तियों में हमारे स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव में अन्य राज्यों की तरह, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि डोमिसाइल की अनिवार्यता की जानी चाहिए।

माननीय सदस्य ने यह भी बात कही है कि शिक्षकों की भर्ती में अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के ही पढ़े हुए लोगों को नौकरी के लिए अनिवार्य किया गया है। उसमें गुजराती माध्यम से पढ़े हुए बच्चों को भी आवेदन करने का मौका दिया जाना चाहिए।

हमारे प्रदेश में हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने नमो मेडिकल कॉलेज की भेंट दी है, जिसमें पीजी के कोर्स स्टार्ट किए गए हैं, परंतु पीजी की फीस 15 लाख रुपये से 25 लाख रुपये रखी गई है, जबकि दिल्ली के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में उसी श्रेणी के पीजी कोर्स की वार्षिक फीस केवल 54 हजार है। (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात खत्म कीजिए।

(व्यवधान)

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल : सभापति महोदया, मैं अपनी बात खत्म कर ही रहा हूँ। हमारा प्रदेश गरीब और आदिवासी बहुल प्रदेश है। हमारे प्रदेश के गरीब लोग इतनी महंगी फीस नहीं भर पाएंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस विषय का संज्ञान लेकर पीजी कोर्स की फीस दिल्ली मेडिकल कॉलेज और देश के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज जितनी करवाने की कृपा करें। साथ ही हमारे प्रदेश के एससी/एसटी, ओबीसी एवं माइनोरिटी सीट्स स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की जाए।